Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

सितम्बर (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **4**

- देश में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भोपाल को दूसरा स्थान 4
- प्रदेश का पहला 500 एमवीए ट्रांसफॉर्मर भोपाल में ऊर्जीकृत 4
- ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफॉर्मर 5
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में चौथी बार मध्य प्रदेश देश में प्रथम 5
- मध्य प्रदेश के दो शिक्षक 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित 6
- 14 शिक्षक उत्कृष्टता के लिये राज्यस्तरीय पुरस्कार से सम्मानित 7
- जनजातीय कार्य विभाग की 'चैंपियन 90' योजना का हुआ शुभारंभ 7
- 'भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोज़गार योजना', 'टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना' एवं 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना' की स्वीकृति 8
- प्रदेश के पहले बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन का शुभारंभ 9
- क्राफ्ट एंड आर्ट प्रदर्शनी 'हस्तकला बाज़ार'का शुभारंभ 9
- भोपाल करेगा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी 9
- आईसीआरटी अवॉर्ड्स में मध्य प्रदेश को मिले चार स्वर्ण और एक रजत अवॉर्ड 10
- विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में होगा 'युवा सेल' का गठन 10
- कूनो पालपुर के विस्थापित ग्रामों को मिलेगा राजस्व ग्राम का दर्जा 11
- शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 98 वर्ष की अवस्था में निधन 12
- प्रदेश में ज़िला वेटलैंड संरक्षण समितियों का गठन 12
- सोलर सिटी और कुसुम योजना के लेटर ऑफ अवार्ड वितरित 13
- ग्वालियर में 1199 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास 13
- स्कूल शिक्षा विभाग का ज़िला रिपोर्ट कार्ड जारी 14
- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ 14
- 9784.95 करोड़ का प्रथम अनुपूरक अनुमान पारित 15
- नवंबर में प्रदेश भर में आयोजित होगी महा उपभोक्ता लोक अदालत 16

नोट :

- मध्य प्रदेश में बनेगा देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल 17
- मंत्रिपरिषद ने मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन की दी स्वीकृति 17
- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मिला राज्यस्तरीय 'मोस्ट प्रोमीनेंट इंडस्ट्री' का अवार्ड 18
- 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' में प्रदेश के 1074 अनुसूचित जाति बहुल ग्राम चयनित 19
- कमर्शियल वाहनों की फिटनेस के लिये बनेंगे ऑटोमेटिव व्हीकल फिटनेस सेंटर 19
- मध्य प्रदेश के पैरा स्वीमर सतेंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्वीमर बने 20
- स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिये मध्य प्रदेश को मिलेंगे कई पुरस्कार 20
- मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में 47 बेटियाँ हुईं सम्मानित 20
- हमीदिया अस्पताल में शुरू होगा आईवीएफ सेंटर 21
- केंद्रीय कृषि मंत्री ने एनएससी के जैविक बीज फार्म का किया शिलान्यास 21
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु एमओयू 22
- आयुष्मान भारत निरामयम योजना में नवाचार और सर्वोत्तम प्रयासों के लिये मध्य प्रदेश हुआ पुरस्कृत 23
- राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में मध्य प्रदेश को मिले 8 पुरस्कार 23
- मंत्रि-परिषद ने दी 17 हज़ार 971 करोड़ से अधिक लागत की जल प्रदाय योजना की स्वीकृति 24
- राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह 25
- भोपाल का पहला जी.आई.एस. अति उच्चदाब सबस्टेशन ऊर्जीकृत 25
- मुख्यमंत्री ने किया 'मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना' का शुभारंभ 26
- किसान क्रेडिट कार्ड होंगे डिजिटल 26

नोट :

मध्य प्रदेश

देश में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भोपाल को दूसरा स्थान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में साइबर अपराध की क्रिप्टो करेंसी संबंधी धोखाधडी की बेहतर और पुख्ता इन्वेस्टिगेशन के लिये भोपाल साइबर पुलिस को देश में दूसरा स्थान प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) नई दिल्ली में गत दिवस किये गए प्रेजेंटेशन में साइबर क्राइम भोपाल की इन्वेस्टिगेशन संबंधी केस-स्टडी को सर्वश्रेष्ठ 10 केस-स्टडी में चुना गया।
- साइबर पुलिस ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किस प्रकार से जापान के क्लाइंट के लिये इंदौर के पीयूष सिंह की कंपनी ने मुख्यत: तीन प्रोडक्ट्स बनाए। इन प्रोडक्ट्स का उपयोग कर कोई भी उपयोगकर्त्ता (EndUser) अपना डिजिटल वालेट (अकाउंट) बना सकता है।
- इस डिजिटल वालेट में वह क्रिप्टो संपत्ति स्टोर कर सकता है और उन्हें निवेश कर सकता है। क्रिप्टोएसेट्स को ट्रांसफर भी कर सकता है तथा उपयोगकर्त्ता को रिवॉर्ड और बोनस मिलता है, जो हर दिन कंपनी के डिजिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है।
- इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जापानी मूल का केशी कुबी, जो कि पीयूष सिंह की कंपनी में ही पूर्व से कार्य करता था, गोपनीय जानकारियों का गलत उपयोग कर पीयूष सिंह के जापानी क्लाइंट के प्रोडक्ट में फर्ज़ी यूज़र बना दिये और उनमें एपीआई के द्वारा क्रिप्टो का फर्ज़ी इन्वेस्टमेंट दिखाया। इससे आरोपी को भी प्रतिदिन रिवॉर्ड मिलने लगे।
- आरोपी anglieum wallet के एक फीचर ote (जिसमें कंपनी यूज़र से ANX लेकर उसी वैल्यू का BTC कंपनी वालेट से यूज़र को देती थी) का यूज़ कर क्रिप्टोकरेंसी ANX को BTC में कनवर्ट करता तथा BTC (BITCOIN) को अपने और अपने परिजनों के क्रिप्टो वालेट में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी करने का कार्य करता रहा। साइबर पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में फर्ज़ी पते को भी डिकोड कर अपराध का पर्दाफाश किया।

प्रदेश का पहला 500 एमवीए ट्रांसफॉर्मर भोपाल में ऊर्जीकृत

चर्चा में क्यों ?

1 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि हाल ही में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 400 केवी सबस्टेशन भोपाल में प्रदेश के पहले 500 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत किया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने नवाचार करते हुए प्रदेश के अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में लगभग 25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पहली बार 500 एमवीए क्षमता के पॉवर ट्रांसफॉर्मर को स्थापित किया है।
- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 400 केवी सबस्टेशन भोपाल में 400/220/132 केवी के 315 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर के लिये लगने वाले स्थान पर ही विशेष डिज़ाइन से तैयार हुए मेसर्स टी एंड आर द्वारा निर्मित इस 500 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफॉर्मर को स्थापित किया है।
- मुख्य अभियंता राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 400 केवी सबस्टेशनों में परंपरागत 315 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाते रहे हैं। इसके स्थान पर पहली बार 500 एमवीए क्षमता का यह पहला पावर ट्रांसफार्मर है, जिसे शासन की ज़्यादा-से-ज़्यादा नवाचार अपनाने की मंशा के तहत स्थापित किया गया है।

नोट :

- इस नवाचार का फायदा यह है कि जितनी जगह 315 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना को लगती है, उतने ही इन्फ्रास्ट्रक्चर में 500 एमवीए क्षमता का ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर लिया जाता है। जिससे अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने की प्रक्रिया, धन और श्रम बच जाता है। साथ ही सबस्टेशनों में बढ़ने वाली अचानक लोड डिमांड को भी पूरा किया जा सकता है। इस ट्रांसफॉर्मर की स्थापना के उपरांत 400 केवी सबस्टेशन भोपाल की क्षमता 1445 एमवीए की हो गई है।
- इस ट्रांसफॉर्मर की स्थापना से भोपाल के शहरी और औद्योगिक क्षेत्र के अलावा बैरागढ़, विदिशा, मुगालिया छाप के अतिरिक्त आष्टा क्षेत्र को भी बेहद फायदा मिलेगा। इस ट्रांसफॉर्मर की स्थापना से इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उचित वोल्टेज में की जा सकेगी। साथ ही, आष्टा, उज्जैन क्षेत्र को भी भोपाल से सपोर्ट मिल सकेगा।

ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफॉर्मर

चर्चा में क्यों ?

4 सितंबर, 2022 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बताया गया कि अब स्वीकृत भार से अधिक भार और अनधिकृत विद्युत के उपयोग की रोकथाम के लिये नवीनतम तकनीक पर आधारित ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफॉर्मर लगने से उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार अथवा अनधिकृत विद्युत का उपयोग करने पर ये वितरण ट्रांसफॉर्मर स्वत: ही बंद हो जाएंगे और बिजली सप्लाई भी रुक जाएगी।
- कंपनी द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपने रिकॉर्ड में दर्ज उपभोक्ताओं की संख्या और उनके वैध स्वीकृत भार के आधार पर निर्धारित क्षमता के ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे, जिससे संबंधित क्षेत्र में अनधिकृत विद्युत का उपयोग संभव नहीं होगा।
- कंपनी ने बताया कि भोपाल के छोला ज़ोन में 100 केवीए का ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है। साथ ही, नर्मदापुरम में मूंग की फसल वाले क्षेत्रों में ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं। इससे वितरण ट्रांसफॉर्मर फेल होने पर अंकुश लगा है। साथ ही, वैध कनेक्शन की संख्या में वृद्धि हुई है तथा कंपनी के राजस्व में भी इजाफा हुआ है।
- कंपनी ने बताया है कि सीहोर वृत्त में एक वितरण केंद्र, जहाँ ट्रांसफॉर्मर फेल होने की दर अधिक थी, वहाँ सभी क्षेत्रों में ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाए जा रहे हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू कर वितरण ट्रांसफॉर्मर बदले जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफॉर्मर से मिलने वाले परिणामों की समीक्षा के बाद कंपनी के अन्य ज़िले भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जाएगा।
- ऑटो कटऑफ वितरण ट्रांसफॉर्मर लगने से वैध उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होने के साथ ही एक ओर जहाँ अनधिकृत विद्युत उपयोग की रोकथाम होगी, वहीं दूसरी ओर कंपनी के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में चौथी बार मध्य प्रदेश देश में प्रथम

चर्चा में क्यों ?

3 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया कि मध्य प्रदेश लगातार चौथे वर्ष प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अमल में वर्ष 2021-22 के लिये राष्ट्रीय स्थान पर प्रथम रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना में मध्य प्रदेश 30 लाख से अधिक हितग्राहियों के पंजीयन, 1294 करोड़ की राशि वितरण और वर्तमान वित्त वर्ष में अगस्त माह तक 2 लाख 26 हज़ार 306 हितग्राहियों को लाभान्वित कर देश में अव्वल है।

नोट :

- बैठक में 'एडॉप्ट एन आँगनवाड़ी'की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आँगनवाड़ी केंद्रों के लिये प्रदेश में खिलौने, अन्य सामग्री सहित 25 करोड़ का जन-सहयोग मिला है। आँगनवाड़ी केंद्रों के लिये आउटडोर खेल सामग्री झूला और फिसलपट्टी आदि का प्रदाय हुआ है। डेढ़ हज़ार से अधिक केंद्र का आदर्श आँगनवाड़ी केंद्र के रूप में उन्नयन किया गया है। बच्चों के लिये जूते-चप्पल और स्वच्छता किट का भी प्रदाय हुआ है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रथम प्रसव की पात्र गर्भवती महिला और धात्री माता को 5 हज़ार रुपए की राशि और द्वितीय प्रसव में बालिका के जन्म पर शिशुवती माता को 6 हज़ार रुपए की राशि दिलवाने का कार्य प्राथमिकता से किया गया है। इसी प्रकार कम वज़न वाले बच्चों का कुपोषण दूर करने के प्रयासों में भी मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है।
- प्रदेश में सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 0 में 6 माह से तीन साल आयुवर्ग के 30 लाख बच्चे पूरक पोषण आहार का लाभ ले चुके हैं। इसी तरह 10 लाख 81 हज़ार गर्भवती और धात्री माताएँ भी लाभान्वित हो चुकी हैं।
- मध्य प्रदेश में टेक होम राशन का लाभ 38 लाख से अधिक हितग्राही ले चुके हैं। वर्तमान में पोषण ट्रैकर पर 71 लाख 20 हज़ार हितग्राहियों का आधार सत्यापन भी पूरा हो चुका है। प्रदेश में 13 संयंत्रों से टेक होम राशन उत्पादन का कार्य हो रहा है। नाश्ता एवं गर्म पका भोजन की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हज़ार से अधिक सांझा चूल्हा समूहों द्वारा की जा रही है।
- शहरी क्षेत्रों में भी 2 हज़ार से अधिक समूह यह कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के 85 हज़ार से अधिक आँगनवाड़ी केंद्रो में पोषण कॉर्नर स्थापित हुए हैं। साथ ही पोषण वाटिकाएँ भी निर्मित की गई हैं।
- मध्य प्रदेश में कम वज़न के बच्चों का कुपोषण दूर करने के मामले में प्रदेश राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे क्रम पर, दुबलेपन के कारण कम वज़न की समस्या के समाधान में तीसरे क्रम पर और ठिगनेपन के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से राष्ट्रीय रैंकिंग में छठवें क्रम पर है।
- कम वज़न के बच्चों की संख्या में जहाँ देश में 7 प्रतिशत की गिरावट हुई है, वहीं प्रदेश में यह गिरावट सर्वाधिक 9.8 प्रतिशत दर्ज हुई है। इसी तरह दुबलेपन के कारण कुपोषण की समस्या में देश में 1.7 प्रतिशत की कमी लाई गई है, वहीं मध्य प्रदेश में 6.8 प्रतिशत कमी लाने में सफलता मिली है। ठिगनेपन के मामलों में भी देश में 3 प्रतिशत की कमी के मुकाबले मध्य प्रदेश में 6.3 की कमी लाने में सफलता मिली है।
- समीक्षा बैठक में लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक योजना में 43 लाख बालिकाओं को लाभ मिला है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में कक्षा 6, 9, 11 और 12 की चार लाख 87 हज़ार 731 बालिकाओं को छात्रवृत्ति की राशि मिली है।

मध्य प्रदेश के दो शिक्षक 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

5 सितंबर, 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के दो शिक्षकों नीरज सक्सेना और ओमप्रकाश पाटीदार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2022 से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस वर्ष देश भर से 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चुना गया था, जिनमें मध्य प्रदेश के दो शिक्षक भी शामिल थे।
- रायसेन ज़िले के शासकीय प्राथमिक शाला सालेगढ़ में पदस्थ शिक्षक नीरज सक्सेना को जनजाति इलाके में शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके जुनून की बदौलत भील जनजाति क्षेत्र के बच्चों के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हुई है। बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार कर उन्होंने एक आदर्श स्कूल स्थापित किया है।
- शाजापुर ज़िले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ विज्ञान के लेक्चरर ओमप्रकाश पाटीदार ने शाजापुर के लिये लोक जैव-विविधता पंजी तैयार करवाई है। उन्होंने विज्ञान को तकनीक से जोड़कर आईसीटी का प्रयोग करते हुए विज्ञान जैसे कठिन विषय को विद्यार्थियों के लिये बेहद सरल बना दिया है।

नोट :

- गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- पुरस्कारों के लिये शिक्षकों का चयन ऑनलाइन तीनस्तरीय चयन प्रक्रिया के ज़रिये पारदर्शी तरीके से किया जाता है।
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।

14 शिक्षक उत्कृष्टता के लिये राज्यस्तरीय पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

5 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रशासन अकादमी स्थित स्वर्ण जयंती ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में प्रदेश के 14 शिक्षकों को 'राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2022' से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने चयनित शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये शॉल, श्रीफल एवं प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया।
- चयनित शिक्षकों में प्राथमिक श्रेणी में 8 एवं माध्यमिक श्रेणी में 6 शिक्षक शामिल हैं। प्राथमिक श्रेणी में ममता शर्मा, शा.प्र.शाला रघुनाथपुरा खिलचीपुर (ज़िला-राजगढ़), के.के.कुल्मी शा.क.मा.वि. दशहरा मैदान (ज़िला-उज्जैन), विपिन कुमार फौजदार स.शि. शा.प्रा.शाला सलगापुर संकुल शाहपुर (ज़िला- नरसिंहपुर), केशरी प्रसाद तिवारी शा.पूर्व मा.वि.मार्तण्ड (ज़िला- रीवा), अरुण कुमार पटेरिया शा.मा. शाला चिकटा (ज़िला- निवाड़ी), सरिता सिंह प्रा.शि. शा.प्रा.शाला बालक (ज़िला-अनूपपुर), घनश्याम प्रसाद यादव मा.शि. शा.क. प्रा. आश्रम शाला चिढ़ार (ज़िला- मंडला) और आशाराम कुशवाहा शा.प्रा.शाला मदनपुर (ज़िला- टीकमगढ़) का सम्मान किया गया।
- इसी प्रकार माध्यमिक श्रेणी में सुधाकर पाराशर प्राचार्य शा.सुभाष उत्कृष्टउ.मा.वि. शिवाजी नगर (ज़िला- भोपाल), विजय कुमार श्रीवास्तव उ.मा.शि. उत्कृष्ट उ.मा.वि.विदिशा (ज़िला- विदिशा), जगदीश गुजराती शा. उत्कृष्ट, उ.मा.वि. बड़वानी (ज़िला- बड़वानी), ज्योत्सना मालवीय शा.हाईस्कूल हुडा (ज़िला- झाबुआ), भूपेंद्र कुमार चौधरी शा. उ.मा.वि. चिमनाखोरी (ज़िला- सिवनी) और सारिका घारू, शा. उ.मा.वि. सॉंडिया (ज़िला- नर्मदापुरम) का सम्मान किया गया।
- दो अन्य शिक्षक राधाकृष्णन केशरी तथा योगेंद्र कोठारी और विशेष श्रेणी में राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान जबलपुर की सुषम्मा जॉनसन को सम्मानित किया गया।
- नवाचार एवं नव अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया, इनमें नर्मदापुरम से नवश्री ठाकुर, आगर मालवा से लोकेश पाटीदार एवं नीमच से मयंक जैन को सम्मानित किया गया।

जनजातीय कार्य विभाग की 'चैंपियन 90' योजना का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

5 सितंबर, 2022 को जनजातीय कार्य आयुक्त संजय सिंह ने नवोदय शासकीय स्कूल कटारा हिल्स में 'चैंपियन-90' योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- अपर संचालक अनुसूचित जाति विकास संजय वार्ष्णेय ने कहा कि 'चैंपियन-90' योजना द्वारा शासकीय विद्यालयों के एससी-एसटी विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक एप्रोच के साथ व्यवस्थित कोचिंग मुहैया कराई जा रही है।
- इस आवासीय कोचिंग में फिटजी की कोचिंग के साथ अंग्रेज़ी और साइकोलॉजी विषय के शिक्षक भी पढ़ाएंगे। सभी बच्चों के भोजन, आवास एवं पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था की जाएगी।

नोट :

- शिक्षक दिवस पर चैंपियन-90 कोचिंग के लिये स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा चयनित 80 बच्चों को फिटजी संस्था द्वारा स्टडी किट और टैबलेट वितरित किये गए।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने निजी कोचिंग संस्थान फिटजी के साथ मिलकर 'चैंपियन-90' पहल शुरू की है। यह संस्थान अपने सी.एस.आर. फंड से इन विद्यार्थियों को सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कोचिंग सुविधा देगा।
- इसके साथ ही हर विद्यार्थी को शैक्षणिक तैयारी के लिये एक टैबलेट भी नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। यह टैबलेट कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक सॉफ्टवेयर से जुड़ा होगा। इसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा सामग्री उपलब्ध होगी। साथ ही, उन्हें अन्य ज़रूरी शैक्षणिक किताबें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

'भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोज़गार योजना', 'टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना' एवं 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना' की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

6 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोज़गार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिये 3 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। इसमें 'भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोज़गार योजना', 'टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना'एवं 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना'शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- 'भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोज़गार योजना'में विनिर्माण गतिविधियों के लिये एक लाख से 50 लाख रुपए तक तथा सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिये एक लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएँ स्वीकृत की जाएंगी।
- योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिये।
- योजना में हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित एवं शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) निगम द्वारा वहन किया जाएगा। आवश्यकतानुसार इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- 'टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना'में ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जो आयकर दाता नहीं हों, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, उन्हें सभी प्रकार की स्व-रोज़गार गतिविधियों के लिये 10 हज़ार से एक लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिये बैंकों से ऋण दिलवा कर हितग्राही को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 5 वर्षों के लिये दिया जाएगा।
- 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना'में मुख्यत: अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये विभिन्न विभागों अथवा ज़िला कलेक्टर से प्राप्त होने वाले ऐसे विशेष परियोजना प्रस्ताव, जो लाइन विभागों की प्रचलित किसी भी योजना परियोजना में किया जाना संभव न हो तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो, को वित्त पोषण के लिये अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की संपूर्ण परियोजना लागत राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
- कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार, आयुष और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आदि से प्राप्त ऐसे विशेष परियोजना प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य परियोजना क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा पर परियोजना लागत राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना में स्व-रोज़गार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन एवं नवाचार संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाएगा। परियोजना में कम-से-कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होना अनिवार्य होगा।

नोट :

प्रदेश के पहले बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

6 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने भोपाल में प्रदेश के पहले 'बकरी पालन को प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास हेतु पशुपालक सम्मेलन' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि आधुनिक तकनीक अपना कर पशुपालन विभाग के सहयोग से बकरी पालन करें और अच्छी आय अर्जित करें। उन्होंने बकरी पालकों को बैंक ऋण लेने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दिया।
- अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी जे.एन. कंसोटिया ने कहा कि प्रदेश में उच्च नस्ल के बकरी वंश को बढ़ाने के लिये कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चिह्नित ज़िलों से आरंभ कर जल्द ही पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा।
- जे.एन. कंसोटिया ने बताया कि कुक्कुट व्यवसाय को पिछले साल से पंजीकृत किया जा रहा है। अब बकरी पालन को भी पंजीकृत किया जाएगा।
- वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि बकरी पालन में मध्य प्रदेश देश में पाँचवें स्थान पर और विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। बकरी की उच्च नस्ल के लिये कृत्रिम गर्भाधान बहुत ज़रूरी है। अच्छी नस्ल का बकरा एक से डेढ़ लाख रुपए में मिलता है। कृत्रिम गर्भाधान से पालक को यह सुविधा हिमीकृत स्ट्रॉ से मात्र 70 रुपए में उपलब्ध होगी।
- संचालक डॉ. आर.के मेहिया ने कहा कि प्रदेश में पिछली पशु गणना के मुकाबले बकरी संख्या में 38 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि बकरी पालन के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है।

क्राफ्ट एंड आर्ट प्रदर्शनी 'हस्तकला बाज़ार'का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

6 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ऊषा ठाकुर ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में क्राफ्ट एंड आर्ट प्रदर्शनी 'हस्तकला बाज़ार' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन बोर्ड द्वारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन में यह प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदेश के 6 कल्चरल ज़ोन से 41 आर्ट फॉर्म के 93 शिल्पकार प्रदर्शनी में अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं।
- 'हस्तकला बाज़ार'प्रदर्शनी में लगभग 16 ज़िलों से 28 शिल्प उत्पाद के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही 6 उत्पाद की लाइव प्रदर्शनी लगाई गई है।
- छतरपुर का टेराकोटा और लौह शिल्प, बैतूल का बैलमेटल, सतना का काँसा, ओरछा की बुंदेली पेंटिंग, देवास का औद्योगिक अपशिष्ट लकड़ी से बनाई गई वस्तुएँ, भोपाल का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और जरी-जरदोजी, राजगढ़ का कपड़ा अपशिष्ट उत्पाद, अलीराजपुर की हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग, खंडवा के हाथ कढ़ाई और कागज़ उत्पाद के साथ महेश्वर हैंडलूम, बांस शिल्प, प्राकृतिक शहद और मार्बल स्टोन की वस्तुएँ प्रदर्शित की गई हैं।

भोपाल करेगा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी

चर्चा में क्यों ?

8 सितंबर, 2022 को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि अगले वर्ष मध्य प्रदेश पहली बार आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग (रायफल/पिस्टल) चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2023 में 20 से 31 मार्च के मध्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शूटर्स भोपाल के बिसनखेड़ी स्थित 'राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस' में अपना हुनर दिखाएंगे।
- मंत्री सिंधिया ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस सभी स्तर से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। अकादमी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज निर्मित है।
- उन्होंने कहा कि शूटिंग विधा में नित नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मध्य प्रदेश अकादमी में उच्च कोटि के अधो-संरचना निर्माण के साथ खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यही कारण है कि अकादमी में देश के प्रतिष्ठित शूटर्स लगातार भोपाल शूटिंग रेंज में प्रशिक्षण के लिये आते हैं।

आईसीआरटी अवॉर्ड्स में मध्य प्रदेश को मिले चार स्वर्ण और एक रजत अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

7 सितंबर, 2022 को राजधानी भोपाल के कुशाभाई ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म (आईसीआरटी) अवॉर्ड्स समारोह में एमपी टूरिज्म बोर्ड ने चार स्वर्ण और एक रजत जीता।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ऊषा ठाकुर ने शिव शेखर शुक्ला (प्रमुख सचिव, पर्यटन और संस्कृति और प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड) और डॉ. हेरोल्ड गुडविन (आईसीआरटी के संस्थापक निदेशक और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप के प्रबंध निदेशक) के साथ विजेताओं को पुरस्कृत किया।
- टूरिज्म बोर्ड के अंतर्गत संचालित ग्रामीण पर्यटन परियोजना, महिलाओं के लिये सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना, रिस्पॉन्सिबल सोवेनियर डेवलपमेंट परियोजना, प्रोजेक्ट हमसफर इत्यादि परियोजनाओं के लिये यह अवॉर्ड दिये गए हैं।
- समारोह में नौ कैटेगरी में कुल 26 अवॉर्ड दिये गए। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को इन्क्रीज डायवरसिटी इन टूरिज्म: हॉउ इन्क्लूजिव इज अवर इन्डस्ट्रीज, ग्रोइंग दि लोकल इकोनॉमिक बेनिफिट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कल्चरल हेरीटेज और इन्क्रीज टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेचुरल हेरीटेज एंड बायोडायवरसिटी कैटेगरी में गोल्ड मिला है। साथ ही, एक्सेस फॉर दि डिफ्रेन्टलीएबल्ड - एज ट्रेवलर्स, इम्पलाइज एंड हॉलीडे मेकर्स कैटेगरी में सिल्वर अवॉर्ड अपने नाम किया।
- उल्लेखनीय है कि आईसीआरटी अवॉर्ड्स रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में से एक है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म (ICRT) द्वारा किया जाता है। खास बात यह है कि यह अवॉर्ड पहली बार लंदन से बाहर हुआ।

विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में होगा 'युवा सेल' का गठन

चर्चा में क्यों ?

8 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यूथ महापंचायत में की गई घोषणानुसार प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में 'युवा सेल'का गठन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- युवा सेल युवा नीति के क्रियान्वयन के लिये विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर होने वाली गतिविधियों की निरंतर समीक्षा और उत्कृष्ट संचालन के लिये आयोजन समिति को सुझाव प्रस्तुत करेगी।
- युवा सेल का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में युवाओं के मध्य सकारात्मक एवं आदर्श वातावरण को निर्मित करना है।

नोट :

- विश्वविद्यालय स्तर पर युवा सेल के संरक्षक कुलपति होंगे। वरिष्ठ संकाय अधिष्ठाता अध्यक्ष एवं समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना सचिव होंगे। संरक्षक द्वारा प्रावीण्यता के आधार पर मनोनीत चार विद्यार्थी, एनएसएस, एनसीसी, खेल-कूद एवं साहित्य-सांस्कृतिक गतिविधि के एक-एक विद्यार्थी, दो एल्यूमनाई, दो अभिभावक (एक महिला, एक पुरुष), एक सांसद तथा एक विधायक प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
- इसी प्रकार महाविद्यालय में युवा सेल के संरक्षक प्राचार्य होंगे। महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक अध्यक्ष, एनसीसी अधिकारी/एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी सचिव, प्रावीण्यता के आधार पर दो स्नातक एवं दो स्नातकोत्तर विद्यार्थी एनएसएस, एनसीसी, खेल-कूद एवं साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल एक-एक विद्यार्थी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। दो एल्यूमनाई, दो अभिभावक (एक महिला एवं एक पुरुष) सदस्य होंगे। सांसद प्रतिनिधि एवं विधायक प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।
- युवा सेल युवा-नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप प्राप्त निर्देशों के परिपालन में कार्य करेगी तथा उसके अनुसार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में आयोजित गतिविधियों का संचालन करेगी।

कूनो पालपुर के विस्थापित ग्रामों को मिलेगा राजस्व ग्राम का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

11 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कूनो पालपुर नेशनल पार्क में आयोजित चीता मित्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कूनो नेशनल पार्क से विस्थापित हुए ऐसे ग्राम जो अभी भी मजरे टोले हैं, उन्हें पूर्ण राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में 5 स्किल डेवलपमेंट केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें क्षेत्रीय युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा।
- गौरतलब है कि कूनो नेशनल पार्क में काफी पहले एशियाटिक लायन को बसाने के लिये स्थानीय दो दर्ज़न गाँवों के सहरिया आदिवासियों को विस्थापित किया गया था।
- श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में अफ्रीकन देश नामीबिया से चीतों को लाकर बसाया जा रहा है। पहले एशियन चीतों को कूनो में बसाने की योजना थी लेकिन ईरान में उनकी सीमित संख्या को देखते हुए अफ्रीका के चीतों को अब कूनो लाया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इसी दिन कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग होगी।
- सरकार के सूत्रों ने बताया कि नामीबिया से 8 चीतों की भारत लाने के लिये MoU किया गया था, लेकिन तीन चीते भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिये हैं, इसलिये पहले चरण में पाँच चीते कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किये जा रहे हैं।
- वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, चीतों को फिर से देश में लाने के लिये लंबे समय से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इसकी मंज़ूरी दी थी। प्रयोग के लिये अफ्रीकन चीतों को भारत के जंगलों में लाया जा रहा है।
- चीतों को भारत लाने की पहल 2010 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने की थी। पहली बार 28 जनवरी, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को भारत लाने की अनुमति दी थी। साथ ही, कोर्ट ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को चीतों के लिये उपयुक्त जगह खोजने का आदेश दिया था। कई राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार के बाद एक्सपर्ट्स ने पृथ्वी पर जाने वाले सबसे पाए तेज जानवर की देश में वापसी के लिये मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को चुना।
- गौरतलब है कि भारत में 70 साल पहले चीते विलुप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आखिरी बार 1950 में चीता देखा गया था। इसके बाद ये देश में कहीं नज़र नहीं आए।
- कूनो पालपुर नेशनल पार्क 750 वर्ग किमी. में फैला है जो कि 6,800 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैले खुले वन क्षेत्र का हिस्सा है। चीतों को फिर से बसाने के लिये देश के सबसे बेहतर पर्यावास में से यह एक है। इसमें चीतों के लिये अच्छे शिकार की सुविधा भी मौज़ूद है, क्योंकि यहाँ हिरण, चिंकारा, नीलगाय, सांभर, लंगूर एवं चीतल बड़ी तादाद में पाए जाते हैं।

नोट :

शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 98 वर्ष की अवस्था में निधन

चर्चा में क्यों ?

11 सितंबर, 2022 को हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु तथा द्वारका-शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

प्रमुख बिंदु

- स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म 2 सितंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में जबलपुर के पास दिघोरी गाँव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
- विदित है कि 'शंकराचार्य'हिंदू धर्म के चार पीठों के सबसे बड़े महंत होते हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी दो मठों (द्वारका एवं ज्योतिर्मठ) के शंकराचार्य थे। माता-पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था।
- नौ वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर धर्म यात्राएँ प्रारंभ कर दी थीं। इस दौरान वह काशी पहुँचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज से वेद-वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली।
- जब 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया तो ये भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और 19 साल की उम्र में 'क्रांतिकारी साधु'के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी दौरान उन्होंने वाराणसी की जेल में नौ महीने और अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश की जेल में छह महीने की सज़ा भी काटी।
- वे करपात्री महाराज के राजनीतिक दल 'राम राज्य परिषद'के अध्यक्ष भी थे। 1940 में वे दंडी संन्यासी बनाए गए और 1981 में उन्हें 'शंकराचार्य' की उपाधि मिली। 1950 में इन्होंने शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड-संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे।
- शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती स्वतंत्रता सेनानी, रामसेतु रक्षक, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाने वाले तथा राम जन्मभूमि के लिये लंबा संघर्ष करने वाले, गोरक्षा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही, रामराज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष, पाखंडवाद के प्रबल विरोधी रहे थे।

प्रदेश में ज़िला वेटलैंड संरक्षण समितियों का गठन

चर्चा में क्यों ?

12 सितंबर, 2022 को राज्य शासन द्वारा ज़िला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में वेटलैंड संरक्षण समितियों का गठन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये और आयुक्त नगर निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम परिषद, नगरीय क्षेत्रों में सदस्य सचिव होंगे।
- सदस्यों में ज़िला वन मंडलाधिकारी, ज़िला भू-बंदोबस्त अधिकारी, अधीक्षण या कार्यपालन या सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल-संसाधन विभाग, संयुक्त संचालक या उप संचालक, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, कृषि, मछली-पालन, क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य वेटलैंड प्राधिकरण एप्को के अधिकारी होंगे।
- ज़िला वेटलैंड संरक्षण समिति के कर्तव्यों में ज़िला स्तर पर तालाबों के समग्र संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में समुचित कार्यवाही करना, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की सहयोगी इकाई के रूप में कार्य करना, ज़िले में वेटलैंड नियम-2017 का प्रभावी क्रियान्वयन, राज्य और केंद्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, मूल्यांकन और निगरानी में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का सहयोग करना शामिल है।
- समिति ज़िले के तालाबों की समस्त जानकारी एकत्र कर डाटाबेस तैयार करेगी और उसके संधारण के लिये भी उत्तरदायी होगी। समिति ज़िले में तालाबों के संरक्षण से जुड़े संबंधित विभागों और हितधारकों के बीच समन्वय करने के साथ चिह्नित डिजिटल वेटलैंड इन्वेंट्री के अनुसार तालाबों की पहचान एवं मैदानी स्तर पर पुष्टि करेगी।

नोट :

- समिति वेटलैंड, तालाब, नदी, अन्य जल-स्रोतों, प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिये लोगों को जागरूक करने के लिये जागरूकता प्रशिक्षण और क्षमता विकास के कार्यक्रमों का आयोजन विश्व वेटलैंड दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस आदि विशेष अवसरों पर करेगी।

सोलर सिटी और कुसुम योजना के लेटर ऑफ अवार्ड वितरित

चर्चा में क्यों ?

13 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाभियान'(कुसुम 'ए'एवं 'सी') के साथ साँची सोलर सिटी सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिये चयनित विकासकों और किसानों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित किया।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिर्राज दंडोतिया ने कुसुम 'ए' योजना में चयनित 9 किसान और डेवलपर को 14 मेगावाट के लेटर ऑफ अवार्ड का वितरण किया।
- साँची के पहाड़ी क्षेत्र की भूमि पर 8 मेगावाट के सौर संयंत्र की स्थापना हेतु डेवलपर नेशनल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक वी.के. सिन्हा ने लेटर ऑफ अवार्ड ग्रहण किया।
- गौरतलब है कि ऊर्जा विकास निगम द्वारा प्रदेश में चिह्नित 900 से अधिक सब-स्टेशनों पर सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिये 4 चरण में लगभग 112 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये चयनित सौर ऊर्जा उत्पादकों के पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ 71 मेगावाट के विद्युत क्रय अनुबंध किये जा चुके हैं।
- मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि कुसुम 'सी'योजना किसान, शासन, जनता और पर्यावरण, सभी के लिये बहुत अच्छी योजना है। किसान बिजली बेचकर आय अर्जित करता है। लगभग 1000 किसानों के पंप सौर ऊर्जीकृत करने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं। किसानों को इससे न केवल सिंचाई की सुविधा मिलेगी बल्कि दिन में बिजली भी मिलेगी।
- योजना में सोलर संयंत्र स्थापना के लिये 30 प्रतिशत केंद्रीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। चयनित डेवलपर्स को 4 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना के लिये परियोजना आवंटन पत्र दिये गए।

ग्वालियर में 1199 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण एवं शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

15 सितंबर, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर में विकास के नए आयाम के रूप में जुड़ने जा रहे एलीवेटेड रोड, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और 122 किमी. लंबी 7 सड़कों सहित लगभग 1199 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई घोषणाएँ भी कीं। ये घोषणाएँ हैं-
- ग्वालियर शहर में स्वर्ण रेखा नदी पर दोनों चरणों का एलीवेटेड रोड अत्याधुनिक मलेशिया से आई नई तकनीक के साथ बनाया जाएगा। एलीवेटेड रोड के दोनों चरण के टेंडर एक साथ निकाले जाएंगे।
- 6 लेन का आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा और मात्र तीन घंटे में दिल्ली से ग्वालियर की दूरी तय की जा सकेगी। लगभग 87 किमी. लंबे इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से होगा।
- आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे के किनारे लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी।
- ग्वालियर-आगरा के पुराने मार्ग का जीर्णोद्धार कर फोरलेन सीमेंट कंक्रीट मार्ग बनाया जाएगा।

नोट :

- ग्वालियर-भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 1200 करोड़ रुपए की लागत से फोरलेन मार्ग में तब्दील किया जाएगा। मुरैना से सबलगढ़ तक 300 करोड़ रुपए की लागत से 72 किमी. लंबा फोरलेन सड़क मार्ग बनाया जाएगा।
- ग्वालियर शहर में फूलबाग से किले तक 120 करोड़ रुपए की लागत से रोप-वे का निर्माण कराया जाएगा। इससे ग्वालियर के पर्यटन विकास में नए आयाम स्थापित होंगे।
- ग्वालियर में जलालपुर-बरौआ के बीच नया रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। आरओबी के निर्माण से जलालपुर एवं बरौआ सहित लगभग 2 दर्जन गाँव को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही शनिश्चरा मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी आवागमन में आसानी रहेगी।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण कर ग्वालियर को फिर से औद्योगिक हब बनाया जाएगा। यहाँ पर आद्योगिक निवेश के साथ पर्यटन, मेडिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने का काम भी किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग का ज़िला रिपोर्ट कार्ड जारी

चर्चा में क्यों ?

15 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ज़िलों की शैक्षिक रैंकिंग प्रणाली विकसित करने के निर्देश अनुसार सत्र 2022-23 में कक्षा पहली से आठवीं तक के लिये ज़िलों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस. ने बताया कि ज़िला रिपोर्ट कार्ड के अनुसार छतरपुर ज़िले को पहला, बालाघाट को दूसरा और छिंदवाड़ा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
- इसी तरह संभाग अनुसार ग्रेडिंग में सागर संभाग को पहला, जबलपुर संभाग को दूसरा और नर्मदापुरम को तीसरा स्थान मिला है।
- संचालक धनराजू एस. ने बताया कि विगत रैंकिंग की तुलना में निवाड़ी ज़िले ने 31 पायदान की छलांग लगाते हुए 10वाँ स्थान प्राप्त किया है। गुना ने पिछली रैंकिंग 51 में सुधार करते हुए इस बार 22वीं रैंक प्राप्त की है।
- रिपोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर अनेक कार्य-बिंदु निर्धारित किये गए हैं। रिपोर्ट में मुख्यत: बच्चों के नामांकन एवं ठहराव, गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक उपलब्धियाँ, शिक्षकों का शैक्षणिक उन्नयन, समानता, अधोसंरचना एवं भौतिक सुविधाएँ और सुशासन प्रक्रियाएँ आदि को 6 मुख्य भागों में बाँटा गया है।
- रैंकिंग में कुल 32 सूचकांक सम्मिलित हैं। प्रत्येक तिमाही की प्राथमिकता के अनुसार सम-सामायिक रुप से परिवर्तन किये जाते रहेंगे।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ

चर्चा में क्यों ?

15 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाल देख-रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक एवं बालिकाओं को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग (आफ्टरकेयर) देकर समाज में पुनर्स्थापित करने और 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना'आरंभ कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के क्रियान्वयन के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
- आफ्टरकेयर के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 5 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे।
- आफ्टरकेयर में आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा के लिये निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जाएगी।

नोट :

- उद्योग विभाग द्वारा ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची में उल्लेखित केयर लीवर्स की योग्यता के अनुसार औद्योगिक संस्थान/प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठित संस्थाओं की पहचान कर इंटर्नशिप देकर उसी संस्था में यथासंभव रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो इंटर्नशिप की अवधि समाप्ति तक या एक वर्ष, जो भी कम हो, तक देय होगी। यह सहायता किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये नहीं होगी।
- पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि में शासकीय संस्थाओं में दी जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण, संबंधित विभाग के द्वारा नि:शुल्क दिये जाएंगे।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि समाप्ति तक या दो वर्ष जो भी कम हो तक देय होगी। किंतु किसी भी दशा में 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये नहीं होगी।
- NEET, JEE या CLAT में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान 5 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिमाह दी जाएगी एवं पाठ्यक्रम अवधि तक फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी।
- केयर लीवर्स की श्रेणी का निर्धारण एवं प्रत्येक श्रेणी में अध्ययन अवधि के दौरान दी जा रही आर्थिक सहायता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
- स्पॉन्सरशिप मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों के लिये है, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो 'मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना'की पात्रता में नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे योजना में पात्र होंगे।
- स्पॉन्सरशिप के तहत पात्र पाए गए प्रत्येक बच्चे को 4 हज़ार रुपए प्रतिमाह की सहायता न्यूनतम एक वर्ष के लिये दी जाएगी। यह राशि बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी।
- बालक अथवा परिवार की आर्थिक समृद्धता में सुधार न होने की स्थिति में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, किंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के बाद राशि देय नहीं होगी। प्रत्येक बच्चे का आयुष्मान कार्ड भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जाएगा।
- योजना के सभी आवेदन बाल आशीर्वाद पोर्टल www.scps.mp.gov.in पर प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। योजना का लाभ लेने के लिये ज़िला कार्यक्रम अधिकारी एवं ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) से संपर्क किया जा सकता है। समस्त लाभ पोर्टल से दिये जाएंगे।

9784.95 करोड़ का प्रथम अनुपूरक अनुमान पारित

चर्चा में क्यों ?

15 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश विधानसभा में 95 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक अनुमान 2022-23 पारित किया गया। राजस्व मद में 6185.46 करोड़ रुपए तथा पूंजीगत मद में 3599.49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस अनुपूरक अनुमान से अधो-संरचनात्मक विकास के कामों में तेजी आएगी। महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिये किये गए कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं -
- आँगनबाड़ी सेवाएँ हेतु 1,003 करोड़ रुपए तथा 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना'हेतु 44 करोड़ रुपए।
- नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजना/परियोजनाओं के लिये 931 करोड़ रुपए। जल संसाधन विभाग की विभिन्न सिंचाई योजनाओं/नहरें/बांध से संबंधित निर्माण कार्य हेतु 608 करोड़ रुपए।
- मुख्यमंत्री शहरी अधो-संरचना विकास योजना- चतुर्थ चरण हेतु 400 करोड़ रुपए।

नोट :

- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित), मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) योजना, मुख्य ज़िला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण, वृहद पुलों का निर्माण योजना तथा अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत योजना हेतु कुल 1100 करोड़ रुपए।
- ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिये 151 करोड़ रुपए।
- कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु 666 करोड़ रुपए, राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु 57 करोड़ रुपए तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (महाविद्यालय तथा अन्य) हेतु 50 करोड़ रुपए।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु 284 करोड़ रुपए। छात्रों के लिये पुस्तकें/स्टेशनरी आदि के प्रदाय योजना हेतु 41 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु 78 करोड़ रुपए।
- अटल गृह ज्योति योजना हेतु 750 करोड़ रुपए तथा अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 750 करोड़ रुपए।
- मुख्यमंत्री पुलिस आवास हेतु हुडको से लिये गए ऋणों के एकमुश्त भुगतान हेतु 280 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति/जनजाति के थानों की स्थापना हेतु 59 करोड़ रुपए, विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत बालाघाट ज़िले को सहायता हेतु 20 करोड़ रुपए।
- ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर कृषकों की ब्याज माफी समाधान योजना हेतु 350 करोड़ रुपए।
- ज़िला माइनिंग फंड योजना के लिये 300 करोड़ रुपए।
- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु 300 करोड़ रुपए।
- मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना हेतु 150 करोड़ रुपए तथा विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता हेतु 81 करोड़ रुपए।
- महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान योजना 2018 हेतु 84 करोड़ रुपए।
- परिसमापक की परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व से भुगतान योजना हेतु 60 करोड़ रुपए तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन ज़िला प्रोत्साहन योजना हेतु 50 करोड़ रुपए।
- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों के लिये 100 करोड़ रुपए। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना तथा विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु 85 करोड़ रुपए।
- दीनदयाल अंत्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु 50 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान हेतु 40 करोड़ रुपए तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण योजना हेतु 38 करोड़ रुपए।

नवंबर में प्रदेश भर में आयोजित होगी महा उपभोक्ता लोक अदालत

चर्चा में क्यों ?

17 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की रजिस्ट्रार अलका श्रीवास्तव ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शांतनु एस. केमकर के मार्गदर्शन में 12 नवंबर, 2022 को महा उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन ज़िला स्तर पर सभी उपभोक्ता अदालतों में किया जायेगा।

प्रमुख बिंदु

- उपभोक्ता संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के लिये 12 नवंबर को महा उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
- अलका श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य आयोग एवं प्रदेश के ज़ला उपभोक्ता आयोगों में विचाराधीन बैंकिंग, बीमा, विद्युत, चिकित्सा, टेलीफोन, कृषि, ऑटोमोबाइल्स, हाउसिंग, एयरलाइंस, रेलवे सहित विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही महा उपभोक्ता लोक अदालत के माध्यम से की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में 17 सितंबर, 2022 को आयोजित बृहद् लोक अदालत स्थगित कर दी गई थी।
- उपभोक्ता संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के लिये 12 नवंबर को महा उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

नोट :

मध्य प्रदेश में बनेगा देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल

चर्चा में क्यों ?

19 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्य समिति की 61वीं बैठक में तय किया गया कि विज्ञान के प्रसार में अग्रणी और प्राचीन उज्जैन नगर में देश के पहले साइंटिस्ट मेमोरियल की स्थापना की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- कार्य समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि प्रदेश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिक नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी तथा विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देते हुए साइंस सिटी और संभाग स्तर पर रीजनल साइंस सेंटर के निर्माण पर फोकस किया जाए।
- परिषद के महानिदेशक ने बताया कि देश में साइंस मेमोरियल तो हैं, लेकिन उज्जैन के तारामंडल में साइंटिस्ट मेमोरियल बनाने का यह पहला प्रकरण है। युवा वैज्ञानिकों की एक प्रतियोगिता में इस तरह का प्रस्ताव आया है। परिषद ने प्रस्ताव पर तत्काल कार्य प्रारंभ करने की सहमति दी है।
- इसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये विज्ञान पर्यटन विकसित करने पर भी चर्चा की गई। जबलपुर और उज्जैन में बनने वाले रीजनल साइंस सेंटर के कार्यों के अनुमोदन के दौरान तय किया गया है कि हर 300 किमी. पर साइंस सेंटर और संभाग स्तर पर रीजनल साइंस सेंटर बनाए जाएंगे।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी ज़िलों में ड्रोन ट्रेनिंग के इंतजाम किये जाएँ और सभी ज़िलों में एक जैसी ट्रेनिंग के स्थान पर ड्रोन की अलग-अलग तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाए। प्रदेश के ज़िलों को ड्रोन ट्रेनिंग के लिये प्रारंभिक तौर पर 10-10 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।
- मंत्री सखलेचा ने ज़िलों के डिजिटल एटलस बनाने की कार्य-योजना की समीक्षा कर निर्देश दिये कि मध्य प्रदेश के एटलस में ज़िले के महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट को शामिल करें। इससे दुनिया से कोई भी यह जान सके कि किस उत्पाद की कहाँ उपलब्धता है। उन्होंने इस कार्य में कॉलेज के विज्ञान विद्यार्थियों का सहयोग लेने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत करने के निर्देश भी दिये।
- मंत्री सखलेचा ने कहा कि देश के ख्यातिलब्ध 15 से 20 वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का एक सलाहकार बोर्ड भी बनाया जाए। यह बोर्ड हर दो माह में रिसर्च और तकनीकी आधारित ज्ञान को साझा करेगा, जो प्रदेश में विज्ञान गतिविधियों के प्रसार में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि युवा और नव उद्यमियों को विज्ञान और तकनीकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिये माह में 2 बार सेमिनार और वेबिनार किये जाएँ।
- समिति में तय किया गया कि बाँस, केला और नारियल से फाइबर बनाने की तकनीक पर काम किया जाएगा। परंपरागत फर्नीचर के स्थान पर मानव की ज़रूरत के मान से फर्नीचर उत्पादन में वैज्ञानिक और तकनीक आधारित बदलाव लाए जाएंगे। साथ ही हेल्थ डाटाबेस तैयार करने पर भी परिषद कार्य करेगी, जिससे स्वास्थ्य बीमा पर होने वाले व्यय को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सके।
- परिषद द्वारा हर वर्ष युवा वैज्ञानिकों को दी जाने वाली कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तर की शोध अध्येतावृत्ति को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। इसमें क्रमश: 5 और 10 हज़ार रुपए की वृद्धि की गई है।
- कार्य-समिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न नवीन आयामों से सतत रूप से सभी विभागों और मंत्रियों को अवगत कराने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। यह भी तय किया गया कि सभी विभागों की संरचना के दृष्टिगत अलग-अलग माड्यूल बनाया जाए।
- बैठक में परिषद में कार्यरत् परियोजना अमले की फेलोशिप में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। संभाग और ज़िला स्तर पर विज्ञान फिल्मों के विकास और निर्माण के साथ ही विज्ञान फिल्म फेस्टीवल किये जाने पर भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन की दी स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

20 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना' में संशोधनों की स्वीकृति देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- संशोधन के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें योजना में 1 बार लाभ प्राप्त हो जाने के बाद और आय की सीमा 6 लाख रुपए से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूरे होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी।
- साथ ही 'लेटरल एंट्री' के माध्यम से इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रदेश की केंद्रीकृत कॉमन मेरिट सूची में प्रथम 15 प्रतिशत में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं 10वीं और 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल से 70 प्रतिशत या सीबीएससी/आईसीएसई की परीक्षा 85 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी यदि आदेश में शामिल संस्थाओं के इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते है, तो ऐसे विद्यार्थी योजना के लिये पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये जेईई मेन्स रैंक की बाध्यता नहीं होगी।
- मंत्रिपरिषद ने ज़िला दतिया में मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (MDTRI) की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दी।
- मंत्रिपरिषद ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय महँगाई-भत्ता एवं राहत की दर में एक अगस्त, 2022 (भुगतान माह सितंबर, 2022) से 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 34 प्रतिशत करने एवं राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत् शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रम, निगम, मंडल तथा अनुदानप्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् चौथे एवं पाँचवें वेतनमान में आनुपातिक आधार पर महँगाई-भत्ते में वृद्धि का 18 अगस्त, 2022 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।
- मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 में पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को महँगाई राहत में वृद्धि के फलस्वरूप व्ययभार मध्य प्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियत अनुपात में वहन किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन की सहमति प्राप्त करने के बाद महँगाई राहत का आदेश जारी करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया गया।
- कर्मचारियों को देय महँगाई-भत्ता में 3 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। पेंशनर/परिवार पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में महँगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष मंठ 304 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिये मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया में गति लाने तथा नई तकनीकों में दक्ष आईटी विशेषज्ञों की सुगम उपलब्धता के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के अंतर्गत संचालित (COE, PeMTS, MPSSDI, CPCT, Email-PMU, TCU, SDC, Security Audit Lab) परियोजनाओं में स्वीकृत पद परिवर्तित करते हुए संविदा अथवा आउटसोर्स से सेवाएँ ली जा सकेंगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मिला राज्यस्तरीय 'मोस्ट प्रोमीनेंट इंडस्ट्री' का अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

20 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल को एसपीएसयू श्रेणी में पूरे प्रदेश में सबसे अधिक शिक्षुओं को शिक्षुता प्रशिक्षण देने के लिये 'मोस्ट प्रोमीनेंट इंडस्ट्री' का अवार्ड प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन सेंटर (मिंटो हॉल) भोपाल में आयोजित आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री के हाथों मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) दिलीप कुमार कापसे ने यह अवार्ड प्राप्त किया।
- गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक 973 ट्रेड शिक्षुओं को इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, कोपा, स्टेनो अंग्रेज़ी एवं स्टेनो हिन्दी जैसे विषयों में कंपनी के अंतर्गत विभिन्न वृत्तों में एकवर्षीय प्रशिक्षण दिया गया है।

नोट :

'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' में प्रदेश के 1074 अनुसूचित जाति बहुल ग्राम चयनित

चर्चा में क्यों ?

- 20 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश जन-संपर्क विभाग द्वारा बताया गया कि 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना'में मध्य प्रदेश के 1074 अनुसूचित जाति बहुल ग्राम का चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2021-22 में योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के 3 ज़िलों का चयन किया गया है, जिसमें गुना ज़िला द्वितीय और सीहोर ज़िला तृतीय स्थान पर है।
- गौरतलब है कि अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों के समेकित विकास के लिये केंद्र सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना'संचालित की जा रही है। योजना में 500 या उससे अधिक आबादी वाले ऐसे गाँवों का चयन किया गया है, जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है।
- आदर्श ग्रामों में ग्रामवासियों को शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का अधिकाधिक लाभ पहुँचाया जाएगा। साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं में सभी व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाना, पात्र व्यक्तियों को निराश्रित, वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशन योजना का लाभ दिलाना, शत-प्रतिशत बच्चों का आँगनबाड़ी तथा शालाओं में प्रवेश कराना, पात्रतानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कराना, प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था, पात्र परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ प्रदान करना और प्रत्येक घर में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना आदि शामिल हैं।
- 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना'में चयनित ग्रामों की अधो-संरचना विकास के लिये बृहद् स्तर पर कार्य किया जाएगा। इसमें ग्राम में शाला भवन, आँगनबाड़ी भवन, आंतरिक सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों के निराकरण की समुचित व्यवस्था आदि शामिल हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम में अधो-संरचना विकास के लिये गैप फिलिंग करने 20 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही राज्य की विभिन्न योजनाओं के साथ सामंजस्य कर ग्राम में अधो-संरचना विकास के कार्य किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि देश में 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना'के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रारंभ से ही शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वर्तमान में 1074 ग्राम के संदर्भ में 5 लाख 53 हज़ार 108 व्यक्तियों को पात्रतानुसार लाभान्वित किया जा चुका है।

कमर्शियल वाहनों की फिटनेस के लिये बनेंगे ऑटोमेटिव व्हीकल फिटनेस सेंटर

चर्चा में क्यों ?

20 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश के 10 संभागीय मुख्यालयों पर लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से कमर्शियल वाहनों की फिटनेस के लिये ऑटोमेटिव व्हीकल फिटनेस सेंटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमुख बिंदु

- परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सेंटर्स की स्थापना से फिटनेस प्रमाण-पत्र देने के पूर्व वाहनों की फिजिकल चेकिंग एक ही स्थान पर हो जाएगी। वर्तमान में वाहनों का फिटनेस मैन्युअली किया जा रहा है।
- गौरतलब है कि वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में ऑटोमेटिव मोटर फिटनेस सेंटर की स्थापना के निर्देश दिये गए हैं।
- एक सेंटर की स्थापना पर लगभग 15 करोड़ रुपए का व्यय होगा। एक सेंटर की स्थापना से एक साल में लगभग 40 हज़ार वाहनों की फिटनेस एवं जाँच की जा सकेगी।
- फिटनेस सेंटर में वाहन की चेकिंग के दौरान पॉल्यूशन, ऑयल लीकेज, ब्रेक, लाइट्स, व्हील अलाइनमेंट, स्पीड गवर्नर आदि की मशीनों से जाँच के बाद ही फिटनेस प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

नोट :

मध्य प्रदेश के पैरा स्वीमर सतेंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्वीमर बने

चर्चा में क्यों ?

20 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के पैरा स्वीमर सतेंद्र सिंह लोहिया आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्वीमर बन गए हैं। सतेंद्र सिंह ने 36 किमी. के नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 39 मिनट में पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग पैरा स्वीमर सतेंद्र सिंह लोहिया ने पूर्व में इंग्लिश और कैटलीना चैनल को पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था और ऐसा करने वाले एशिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग पैरा स्वीमर बने थे। अब नॉर्थ चैनल पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक भी बन गए हैं।
- सतेंद्र ने नॉर्थ आयरलैंड के समयानुसार सुबह 6:31 बजे और भारतीय समयानुसार 11:00 बजे नॉर्थ चैनल समुद्र में तैराकी शुरू की थी। यह नॉर्थ चैनल नार्दनलैंड के डोनगड़ी और पोर्ट पेट्रियट स्कॉटलैंड के बीच की 36 किमी. दूरी की तैराकी है। इस चैनल की खासियत है कि यह विश्व के सभी चैनलों में सबसे ठंडा चैनल है। इसका तापमान 12 डिग्री सें. के लगभग रहता है।
- गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्वीमर सतेंद्र सिंह लोहिया ने 24 जून, 2018 को 12 घंटे 24 मिनट में 49 किमी. लंबे इंग्लिश चैनल को पार किया था। इसके लिये उनका नाम एशियाई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। अमेरिका में 18 अगस्त, 2019 को उन्होंने 11 घंटे 34 मिनट में 42 किमी. लंबे कैटलीना चैनल को पार किया था।
- सतेंद्र सिंह ने 7 नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में भाग लेकर देश के लिये 24 पदक हासिल किये हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2014 में उन्हें सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से नवाजा था। इसके बाद 3 दिसंबर, 2019 को उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था। सतेंद्र सिंह लोहिया को पीएम नरेंद्र मोदी भी सम्मानित कर चुके हैं।

स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिये मध्य प्रदेश को मिलेंगे कई पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिये मध्य प्रदेश को कई पुरस्कारों के लिये चुना गया है। राष्ट्रपति द्वारा 2 अक्टूबर को विज्ञान भवन, दिल्ली में होने वाले स्वच्छ भारत दिवस पर ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के दल को प्रदान किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2022 में वेस्ट ज़ोन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान, उत्कृष्ट कार्य करने वाले ज़िलों में भोपाल को प्रथम एवं इंदौर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।
- इसी प्रकार सुजलाम अभियान-1 में श्रेष्ठ कार्य के लिये मध्य प्रदेश को प्रथम एवं सुजलाम अभियान-2 में मध्य प्रदेश को चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में 47 बेटियाँ हुईं सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

22 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने 'मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान' में आयोजित लाड़ली लक्ष्मी सम्मेलन में 47 बेटियों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- 'लाड़ली लक्ष्मी सम्मेलन' में 11 बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी प्रमाण-पत्र, 25 परिवारों को एकल बेटी परिवार सम्मान, 13 बालिकाओं को जिमनास्टिक में राज्यस्तरीय गोल्ड मेडल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताईक्वांडो में मेडल, गोला फेंक में गोल्ड मेडल, एयरोबिक्स नेशनल प्लेयर गोल्ड मेडल, नेशनल कराटे चैंपियनशिप, ऑल इंडिया कराटे में गोल्ड मेडल, योग में गोल्ड मेडल इत्यादि उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये सम्मान, 3 बालिकाओं को 'मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना' का लाभ और 5 युवतियों को पिंक लाइसेंस प्रदान किये गये।

नोट :

- सम्मेलन में गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभों से वंचित रह गए हितग्राहियों को पात्रता अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। इन्हें केंद्र और राज्य सरकार की 33 जन-कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म-दिन 17 सितंबर से 31 अक्टूबर (45 दिन) तक 'मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान' चलाया जा रहा है।
- 'मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान'से प्रत्येक ज़रूरतमंद पात्र व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करने का संकल्प लिया गया है। अभियान में संकल्प पूर्ति के लिये घर-घर पहुँच कर लोगों से जानकारी लेकर लाभान्वित करने का महती कार्य किया जा रहा है।
- गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 'लाड़ली लक्ष्मी योजना'के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। बालिकाओं के प्रति न केवल लोगों की सोच में बदलाव आया है, बल्कि लिंगानुपात में भी उत्तरोत्तर सुधार हुआ है।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में इंदौर प्रदेश में अव्वल नंबर पर है। इंदौर में एक लाख 81 हज़ार बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है।
- जल-संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि पूरा देश मध्य प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी योजना का अनुसरण कर रहा है। वर्ष 2007 से प्रारंभ हुई इस योजना से 43 लाख बालिकाएँ लाभान्वित हो रही हैं।

हमीदिया अस्पताल में शुरू होगा आईवीएफ सेंटर

चर्चा में क्यों ?

23 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के नए भवन में आईवीएफ सेंटर शुरू किये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री सारंग ने हमीदिया अस्पताल के निरीक्षण के बाद कहा कि हमीदिया अस्पताल में स्थानांतरित किये गए सुल्तानिया अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में आईवीएफ सेंटर शुरू किया जाएगा। इस सेंटर के माध्यम से प्रदेश के गरीब नि:संतान दंपतियों को लाभ मिल सकेगा।
- उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर में पहली बार ऐसा कदम उठाया जा रहा है। आईवीएफ सेंटर के लिये बजट का प्रावधान कर स्थान का चिह्नांकन कर दिया गया है। सेंटर की स्थापना में लगभग 4 माह का समय लगेगा।
- मंत्री सारंग ने कहा कि हमीदिया अस्पताल में लगभग 2000 फीट की जगह में आईवीएफ लैब बनाई जाएगी। इसके लिये चिकित्सकों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ को अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे सेंटर पर आने वाले गरीब नि:संतान दंपतियों का उचित उपचार सुनिश्चित हो सकेगा।
- मंत्री ने कहा कि आईवीएफ की प्रक्रिया में लाखों का व्यय होता है। ऐसे में प्रदेश के गरीब दंपती जो संतान सुख से वंचित होते हैं, उन्हें हमीदिया अस्पताल में आईवीएफ के जरिये जल्द ही लाभ मिल पाएगा। इसके लिये आईवीएफ लैब में शोध के साथ इलाज भी किया जाएगा। ऐसी महिलाएँ जो माँ नहीं बन पा रही हैं, वे कम खर्च में जाँच कराकर इस सुविधा का लाभ ले सकती हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने एनएससी के जैविक बीज फार्म का किया शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

25 सितंबर, 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया। इसके प्रारंभ होने पर मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध होंगे।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने मुरैना में जैविक बीजों के उत्पादन के लिये बीहड़ क्षेत्र में भूमि सुधार कर फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मुरैना के 4 गाँवों गडोरा, जाखौना, रिठौरा खुर्द और गोरखा में 34 हेक्टे. जमीन आवंटित की गई है।

नोट :

- केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मुरैना में जैविक बीजों के उत्पादन के लिये फार्म विकसित करने की जिम्मेदारी एनएसपी को सौंपी है। इस फार्म से किसान आधुनिक पद्धतियों से अवगत होंगे। उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे।
- मुरैना में रेवाइंस क्षेत्र में बीज उत्पादन से भूमि में सुधार होगा व भूमि उपजाऊ होगी। स्थानीय किसान भूमि सुधार से प्रेरित होकर अपने खेतों में भी भूमि सुधार कर नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति से बीज उत्पादन कर खेती में कम लागत से उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- एनएससी के विशेषज्ञों द्वारा स्थानीय और प्रदेश के किसानों को ट्रेनिंग के जरिये नवीनतम बीज उत्पादन तकनीक सिखाई जाएगी। स्थानीय श्रमिकों को फार्म में भूमि सुधार एवं बीज उत्पादन से रोज़गार प्राप्त होगा। किसानों को नवीनतम एवं आनुवंशिक व भौतिक रूप से शुद्ध जैविक तिलहन बीज प्राप्त होने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, जिससे न केवल प्रदेश के कृषकों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार होगा, बल्कि कृषकों को पोषण सुरक्षा भी प्राप्त होगी।
- केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मुरैना का बीज फार्म किसानों की प्रगति के लिये विज्ञान व अनुसंधान का पूरा उपयोग करेगा। बीज कृषि का आधार व प्रमुख आदान है। उन्होंने कहा कि खेती के लिये अच्छे बीजों की उपलब्धता से उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिये उच्च आय के अलावा एग्री इको-सिस्टम व अर्थ-व्यवस्था को समग्र रूप से लाभ होता है।
- केंद्र सरकार, राज्यों में बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विविध योजनाओं द्वारा बीज वितरण में सहायता करती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसलों के गुणवता वाले बीज उत्पादन और गुणन बढ़ाने के लिये 2014-15 से बीज और रोपण सामग्री सब मिशन लागू किया है, ताकि किसानों को पर्याप्त बीज मिलें।
- बीज संबंधी विभिन्न गतिविधियों के जरिये राज्यों व सार्वजनिक क्षेत्र के बीज संगठनों को, बीज गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत किया जा रहा है। बीते 8 साल में व्यावसायिक खेती के लिये 304 किस्में अधिसूचित की गई हैं।
- केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य की 207 हेक्टेयर भूमि को डी-नोटिफिकेशन करने की अनुशंसा का बड़ा फैसला लिया है। इस अभयारण्य क्षेत्र के राजस्व भूमि होने से रेत की उपलब्धता के कारण स्थानीय स्तर पर रोज़गार भी बढ़ेंगे।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु एमओयू

चर्चा में क्यों ?

26 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और नेशनल कोएलीशन फॉर नेचुरल फार्मिंग (एनसीएनएफ) के मध्य प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के लिये एमओयू साइन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- एमओयू के तहत किसानों को जागरूक करने में एनसीएनएफ समान विचारधारा वाली 23 पार्टनर संस्थाओं के साथ मिल कर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को लाभान्वित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- प्राकृतिक खेती के लिये एनसीएनएफ द्वारा नेचर पॉजीटिव एग्रीकल्चर एवं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा शासन के साथ पॉलिसी एवं क्रियान्वयन के स्तर पर भी सशक्त भागीदारी की जाएगी।
- गौरतलब है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 40 हज़ार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, जैविक उत्पादन, उचित मूल्य प्राप्त करने, जीवामृत, बीजामृत, गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट और रोगों एवं कीटों की रोकथाम के लिये जैविक कीटनाशक तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- प्राकृतिक खेती के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के बेहतर बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। निरंतर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्षीण हो रही भूमि की उर्वरा शक्ति, नष्ट हो रहे कृषि मित्र केचुएँ और जन्म ले रही मानवजन्य बीमारियों की रोकथाम के लिये प्रदेश में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- प्राकृतिक खेती के रकबे को बढ़ा कर खेती की लागत में कमी लाते हुए किसानों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिये शासन निरंतर कार्य कर रहा है।

नोट :

आयुष्मान भारत निरामयम योजना में नवाचार और सर्वोत्तम प्रयासों के लिये मध्य प्रदेश हुआ पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

26 सितंबर, 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आरोग्य मंथन 2022 कार्यक्रम के समापन-सत्र में मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत निरामयम और स्वास्थ्य योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के चार वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एक वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली में 25 सितंबर और 26 सितंबर को आयोजित दोदिवसीय 'आरोग्य मंथन'कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया गया।
- प्रदेश को वर्ष 2021-22 में आयुष्मान भारत योजना में 'नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य'के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत निरामयम और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में मध्य प्रदेश द्वारा किये गए अनुकरणीय कार्य और प्रगति की सराहना की है।
- प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम योजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रतिदिन 4 हज़ार से अधिक लाभार्थियों को नि:शुल्क उपचार दिया जा रहा है। राज्य एम्बुलेंस सेवा से योजना के पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क परिवहन प्रदाय किया जा रहा है।
- योजना में लाभार्थी केंद्रित 26 लाइन इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर स्थापित किये गए हैं। इनबाउंड कॉल सेंटर से लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सूचना प्रदाय की जा रही है। समवर्ती लेखा परीक्षा और लाभार्थी फीडबैक लेने के लिए आउटबाउंड कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।
- पीएमजेएवाई फंड से सरकारी अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। निरामयम प्रोत्साहन योजना में पंजीकृत होने वाले प्रत्येक प्रकरण के लिये चिकित्सक और उपचार करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। रोगी कल्याण समितियों में जमा घ्हुई राशि से अस्पतालों के बुनियादी ढाँचों को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य शासन ने अस्पतालों को इलाज के लिए पर्याप्त पैकेज लागत उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2.2 कार्यक्रम को अपनाया है।

राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में मध्य प्रदेश को मिले 8 पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

27 सितंबर, 2022 को विश्व पर्यटन दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19' के तहत मध्य प्रदेश को 8 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- 'सिविक मैनेजमेंट ऑफ ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया' (कैटेगरी ए) के लिये देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को पुरस्कार मिला। इस कैटेगरी में प्रदेश को अब तक 7 अवार्ड मिल चुके हैं। 2010-11 और 2011-12 में मांडू, 2012-13 में पचमढ़ी, 2013-14 में महेश्वर, 2015-16 में खरगोन (कैटेगरी बी) और 2016-17 में ओंकारेश्वर (कैटेगरी बी) सम्मानित हो चुके हैं।
- 'स्वच्छ पर्यटन स्थान-वेस्टर्न रीजन' की श्रेणी में पहली बार पुरस्कार नगर निगम उज्जैन को मिला।
- 'बेस्ट मेंटेंड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मॉन्यूमेंट' के लिये शिव मंदिर, भोजपुर को अवार्ड मिला। इसके पहले 2017-18 में साँची स्तूप, 2014-15 में अमरकंटक मंदिर और 2013-14 में शिव मंदिर भोजपुर के लिये प्रदेश को यह सम्मान मिल चुका है।मध्य प्रदेश को मिले 8 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार इस प्रकार हैं-
- 'बेस्ट एयरपोर्ट-रेस्ट ऑफ इंडिया' के लिये देवी अहिल्या बाई एयरपोर्ट, इंदौर को लगातार तीसरी बार यह सम्मान मिला है।
- 'एक्सीलेंस इन पब्लिशिंग-हिंदी' कैटेगरी के लिये मालवा के भित्ति चित्र को अवार्ड मिला है। इसके पहले 2015-16 में सिंहस्थ ब्रोशर के लिये यह सम्मान दिया गया था।

नोट :

- 'बेस्ट टूरिज्म प्रमोशन पब्लिसिटी मटेरियल' के लिये भोपाल ब्रोशर को यह अवार्ड मिला है। इसके पहले 2017-18 में लोनली प्लेनेट पॉकेट बुक्स और 2010-11 में एमपीएसटीडीसी के कॉर्पोरेट ब्रोशर के लिये यह सम्मान मिला है।
- 'बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड, वेस्टर्न-सेंट्रल' के लिये पेंच टाइगर रिज़र्व के गाइड श्री सुभाष भावरे को अवॉर्ड मिला है। 2017-18 में पन्ना से श्री मनोज कुमार द्विवेदी, 2016-17 में पन्ना से राधिका प्रसाद ओमरे और 2015-16 में सतपुड़ा से सईब खान को यह अवार्ड मिल चुका है।
- 'इंक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट्स अप्रूव्ड बाय स्टेट गर्वमेंट' के लिये मंडला ज़िले के कान्हा नेशनल पार्क स्थित गाँव पटपरा के होमस्टे 'कोटयार्ड हाउस'को अवार्ड मिला है।
- प्रदेश को 'स्वच्छ पर्यटन स्थान- वेस्टर्न रीजन'(उज्जैन) और 'इंक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट अप्रूव्ड बाय स्टेट गर्वमेंट'(कोटयार्ड हाउस 'होमस्टे, मंडला) कैटेगरी में पहली बार अवार्ड मिले है। 'बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड'के लिये लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश के गाइड सम्मानित हुए हैं।

मंत्रि-परिषद ने दी 17 हज़ार 971 करोड़ से अधिक लागत की जल प्रदाय योजना की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

27 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिये 17 हज़ार 971 करोड़ 95 लाख रुपए लागत की प्रस्तावित 23 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाओं तथा एक पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद ने 10×40 मेगावाट महेश्वर जल विद्युत परियोजना, ज़िला खरगोन के संबंध में समन्वय में मुख्यमंत्री से प्राप्त निर्णयों का अनुसमर्थन किया।
- महेश्वर जल विद्युत परियोजना से विद्युत क्रय हेतु तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल (वर्तमान में एमपीपीएमसीएल) द्वारा क्रमश: 11 नवंबर, 1994 एवं 27 मई, 1996 को मेसर्स श्री महेश्वर हायडल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएमएचपीसीएल) के साथ निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध एवं इस अनुबंध के संशोधन को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मेसर्स एसएमएचपीसीएल एवं विद्युत मंडल (वर्तमान में एमपीपीएमसीएल) के मध्य परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कार्यों के संबंध में 24 फरवरी, 1997 को निष्पादित अनुबंध को निरस्त किया गया।
- मेसर्स एसएमएचपीसीएल द्वारा महेश्वर परियोजना के वित्त पोषण हेतु जारी किये गए 400 करोड़ रुपए के ओएफसीडी हेतु पीएफसी द्वारा दी गई गारंटी के परिप्रेक्ष्य में अमेंडेटरी एंड रिस्टेटेड एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन द्वारा पीएफसी के पक्ष में दी गई काउंटर गारंटी को निरस्त किया गया।
- पीएफसी, मेसर्स एसएमएचपीसीएल इत्यादि के साथ 16 सितंबर, 2005 को निष्पादित अमेंडेटेरी एंड रिस्टेटेड एग्रीमेंट (ए. एंड आर. अनुबंध) को मेसर्स एसएमएचपीसीएल द्वारा किये गये डिफाल्ट्स के दृष्टिगत निरस्त किया।
- मेसर्स एसएमएचपीसीएल के साथ 27 मई, 1996 को निष्पादित इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट एवं उनके विद्युत देयकों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई गारंटी को निरस्त किया गया।
- महेश्वर परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष द्वारा परियोजना के निराकरण हेतु सुझाए गए द्वितीय विकल्प यथा प्रकरण का निराकरण पीएफसी द्वारा एनसीएलटी में प्रस्तुत की गई आईबीसी पिटीशन में होने दिया जाये, को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद ने 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना'को और अधिक प्रभावी तथा व्यापक बनाने न्यूनतम परियोजना सीमा को एक लाख से कम कर 50 हज़ार रुपए किये जाने का निर्णय लिया।

नोट :

- योजना में अब हितग्राही को ब्याज अनुदान वार्षिक के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। विनिर्माण इकाई 50 लाख रुपए से अधिक होने अथवा सेवा/खुदरा व्यवसाय इकाई 25 लाख रुपए से अधिक होने पर भी योजना में परियोजनाएँ स्वीकार की जाएगी, जिसमें बैंक द्वारा प्रकरण स्वीकृति की दशा में हितग्राही को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ अधिकतम 50 लाख अथवा 25 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर ही प्राप्त हो और ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति भी यथानुपात आधार पर हो। बैंक द्वारा दिया गया पूरा ऋण कोलेटरल फ्री होना चाहिये।
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अर्हता एवं वित्तीय सहायता के लिये आयु सीमा मूलत: 18 से 40 वर्ष रखी गई थी, जिसको संशोधित कर अब 18 वर्ष से 45 वर्ष करने के आदेश का अनुमोदन किया गया।

राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह

चर्चा में क्यों ?

28 सितंबर, 2022 को इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में तीन विभूतियों को वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिये राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- अलंकरण समारोह में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2019 का पार्श्व गायन के लिये शैलेंद्र सिंह, वर्ष 2020 का संगीत निर्देशन के लिये आनंद-मिलिंद और वर्ष 2021 का पार्श्व गायन के लिये कुमार शानू को प्रदान किया गया।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अलंकरण समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि इंदौर में 'भारत रत्न'लता मंगेशकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि लता जी के गीत और स्मृतियों का संग्रह करने के लिये एक संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और उनके नाम से संगीत अकादमी एवं संगीत महाविद्यालय भी प्रारंभ किया जाएगा।
- पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप इंदौर के संगीत महाविद्यालय को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के नाम पर किया जा रहा है। अब यह विद्यालय 'लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय'के नाम से जाना जाएगा।

भोपाल का पहला जी.आई.एस. अति उच्चदाब सबस्टेशन ऊर्जीकृत

चर्चा में क्यों ?

28 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भोपाल की अरेरा कॉलोनी में प्रदेश का दूसरा तथा भोपाल का पहला जी.आई.एस. (गैस इंसूलिटेड स्विच गियर सबस्टेशन) अति उच्चदाब सबस्टेशन को ऊर्जीकृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने नवाचार करते हुए भोपाल के पारेषण नेटवर्क को मज़बूती और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिये इस अति उच्चदाब सबस्टेशन का निर्माण किया है।
- करीब 38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भोपाल की घनी आबादी स्थित ई-8 अरेरा कालोनी में 50 एम.वी.ए. क्षमता के साथ इस सबस्टेशन को ऊर्जीकृत किया गया।
- ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इस सबस्टेशन के प्रारंभ हो जाने से मध्य भोपाल क्षेत्र में विद्युत पारेषण व्यवस्था को मज़बूती मिलने के साथ भोपाल को अति उच्चदाब सबस्टेशन का एक और विकल्प उपलब्ध हो गया है। भोपाल शहर में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी का यह 11वाँ अति उच्चदाब सबस्टेशन है, जो क्रियाशील है।

नोट :

- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक इंजी. सुनील तिवारी ने बताया कि भोपाल जैसी घनी आबादी में परंपरागत सबस्टेशन और लाइनों के निर्माण के लिये पर्याप्त भूमि की उपलब्धता न रहने के कारण मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भोपाल में जी.आई.एस. सबस्टेशन (गैस इंसूलिटेड स्विच गियर सबस्टेशन) तैयार करने का निर्णय लिया।
- जी.आई.एस. सबस्टेशन (गैस इंसूलिटेड स्विच गियर सबस्टेशन) के निर्माण में परंपरागत एयर इंसुलेटेड सबस्टेशनों के मुकाबले कम भूमि की ज़रूरत पड़ती है। इस तकनीक से सबस्टेशन के निर्माण का बजट परंपरागत सबस्टेशन की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक रहता है। गैस इंसुलेटेड चैंबर में रहने के कारण इन सबस्टेशनों के उपकरणों में कम खराबी आती है। इन्हें बोलचाल की भाषा में 'मेंटीनेंस फ्री 'सबस्टेशन भी कहा जाता है।

मुख्यमंत्री ने किया 'मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

29 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर ज़िले के बुधनी विकासखंड की ग्राम पंचायत तालपुरा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में 'मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना 'का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि डेयरी व्यवसाय से प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि करने और वे पशुपालन कर अधिक-से-अधिक आय अर्जित कर सकें, इसके लिये मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया गया है। पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना प्रदेश के तीन ज़िलों-सीहोर, विदिशा और रायसेन में शुरू की गई है।
- पहले से ही पशुपालन का कार्य कर रहे पशुपालकों को मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में दो मुर्रा भैंसे उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 10 लीटर प्रतिदिन की होती है। मुर्रा भैंसों की लागत दो लाख 50 हज़ार रुपए होगी।
- योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान एवं पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
- इस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पशुपालकों को अंशदान के रूप में 62 हज़ार 500 रुपए तथा पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी वालों को एक लाख 50 हज़ार रुपए जमा करने होंगे। इसमें पशुपालकों के आने-जाने का व्यय एवं बीमा आदि की राशि भी शामिल है।

किसान क्रेडिट कार्ड होंगे डिजिटल

चर्चा में क्यों ?

29 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है। पद्धति के कंप्यूटरीकरण से केसीसी ऋण देने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा, जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल होगी।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि हरदा ज़िले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभव के आधार पर इसे प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी लागू किये जाने पर विचार किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि इस पद्धति के लागू होने से किसान को क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिये बैंक शाखा में जाने एवं किसी प्रकार के दस्तावेज को जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी।
- आवेदन ऑनलाइन ऐप से किये जा सकेंगे। साथ ही, कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन हो जाता है। प्रकरण का अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होने से किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकते हैं।

नोट :